



Drishti IAS



करेंट अफेयर्स

उत्तर प्रदेश

जुलाई

2024

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश	3
➤ ABHA ID के माध्यम से सर्वाधिक टोकन	3
➤ उत्तर प्रदेश में फसल-विशिष्ट बोर्ड स्थापित किये जाएंगे	4
➤ पुतिन ने हाथरस भगदड़ त्रासदी पर संवेदना व्यक्त की	4
➤ काशी में एग्री जंक्शन केंद्र खुलेंगे	5
➤ उत्तर प्रदेश सरकार का रक्षा सौदा	6
➤ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा	7
➤ दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर उत्तर प्रदेश	8
➤ वाराणसी में ब्लैक कार्बन के स्तर में कमी	9
➤ न्यूरोलॉजिकल डिस्ऑर्डर का शीघ्र पता लगाना	10
➤ हाइब्रिड कारों पर कोई रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं	11
➤ आम की प्रूनिंग का परमिट रद्द	11
➤ सारस क्रेन की संख्या में वृद्धि	12
➤ अल्ट्रा हाई-परफॉरमेंस कंक्र्रीट- UHPC	13
➤ दृष्टिहीनों के लिये नया यूजर इंटरफेस	14
➤ अर्ली लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम	14
➤ सौश्रुतम 2024	15
➤ काँवड़ यात्रा	16
➤ कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना	16
➤ उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे 3.72 करोड़ पौधे लगाए जाएँगे	17
➤ उत्तर प्रदेश के लिये औद्योगिक लाभ	18
➤ वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय का ब्राजील के साथ समझौता ज्ञापन	19
➤ IIT-कानपुर के प्रोफेसर ने बहिर्ग्रह (Exoplanet) की खोज की	19
➤ भारत में 628 बाघों की मृत्यु	20

उत्तर प्रदेश

ABHA ID के माध्यम से सर्वाधिक टोकन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) ID के माध्यम से एक करोड़ टोकन सृजित करके कीर्तिमान स्थापित किया है।

मुख्य बिंदु:

- उत्तर प्रदेश एकमात्र भारतीय राज्य है जिसने अब तक कुल 1,43,00,000 टोकन सृजित करने की उपलब्धि हासिल की है।
 - उत्तर प्रदेश के बाद, आंध्र प्रदेश 60,33,104 टोकन के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि कर्नाटक 42,57,944 टोकन के साथ तीसरे स्थान पर है।
- वर्ष 2007 में शुरू किये गए और वर्ष 2022 में नवीनतम अद्यतन किये गए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (IPHS) दिशा-निर्देश प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु गुणवत्ता मानक निर्धारित करते हैं।
 - ये मानक पूरे देश में सुसंगत, सुलभ और जवाबदेह स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करते हैं।
 - स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्वास्थ्य संस्थानों को IPHS मानकों के अनुपालन की त्वरित निगरानी करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने में सहायता करने के लिये एक डैशबोर्ड बनाया है।

आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स (ABHA)

- ABHA ID एक अद्वितीय 14-अंकीय संख्या है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने के लिये किया जाता है। यहाँ ABHA से तात्पर्य एक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने से है, इसका लक्ष्य स्वास्थ्य देखभाल के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है।
- कोई भी व्यक्ति निशुल्क स्वास्थ्य ID या ABHA के लिये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) में नामांकन कर सकता है।
- विशेषताएँ
 - इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (EHR): ABHA इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को एकीकृत करता है, जिससे रोगी की जानकारी के संग्रह और पुनर्प्राप्ति की सुविधा मिलती है।
 - इससे चिकित्सा इतिहास को बनाए रखने और स्वास्थ्य सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने में सहायता मिलती है।
 - पोर्टेबिलिटी: एकाउंट्स को आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में परिवर्तित (पोर्टेबल) होने के लिये डिजाइन किया गया है, जिससे लाभार्थियों को स्थान की परवाह किये बिना सेवाओं तक निर्बाध पहुँच की अनुमति मिलती है।
 - पारदर्शिता और जवाबदेही: डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए रखने से ABHA स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही में वृद्धि होती है।

उत्तर प्रदेश में फसल-विशिष्ट बोर्ड स्थापित किये जाएंगे

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार 50,000 करोड़ रुपये के वार्षिक कृषि निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम के रूप में फसल-विशिष्ट वस्तु बोर्ड स्थापित करने की योजना बना रही है।

मुख्य बिंदु

- इस पहल का उद्देश्य अगले चार वर्षों में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण को उत्प्रेरित करना और कृषि मूल्य शृंखला को पुनः सक्रिय करना है।
 - रोजगार सृजन के लिये सरकार कृषि-केंद्रित स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है।
 - राज्य में स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट और फूलों जैसे बागवानी उत्पादों की भारी मांग है।
- भारतीय मसाला बोर्ड की तर्ज पर राज्य स्तरीय बागवानी वस्तु बोर्ड स्थापित किये जाएंगे।
- भारतीय खाद्य एवं कृषि चैंबर (Indian Chamber of Food and Agriculture- ICFA) ने कृषि उद्योग और निर्यात को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य कृषि परिषद का गठन किया है।
 - इससे सरकार, कृषि विशेषज्ञों और किसानों के बीच समंवय को बढ़ावा मिलेगा।
 - परिषद सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, बाजार पहुँच बढ़ाने और निर्यात को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
 - यह फरवरी 2025 में लखनऊ में 'एग्रो वर्ल्ड 2025' शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

भारतीय मसाला बोर्ड

- मसाला बोर्ड का गठन 26 फरवरी, 1987 को मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के अंतर्गत तत्कालीन इलायची बोर्ड (वर्ष 1968) और मसाला निर्यात संवर्द्धन परिषद (वर्ष 1960) के विलय से किया गया था।
- वाणिज्य विभाग के अंतर्गत पाँच वैधानिक कमोडिटी बोर्ड हैं।
 - ये बोर्ड चाय, कॉफी, रबर, मसालों और तंबाकू के उत्पादन, विकास तथा निर्यात के लिये जिम्मेदार हैं।
- यह 52 अनुसूचित मसालों के निर्यात संवर्द्धन और इलायची के विकास के लिये जिम्मेदार है।
- मसाला बोर्ड भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी प्रचार-प्रसार के लिये प्रमुख संगठन है।
- बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेशी आयातकों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी है।

भारतीय खाद्य एवं कृषि चैंबर (ICFA)

- पूर्व में भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद के नाम से जानी जाने वाली भारतीय खाद्य एवं कृषि चैंबर की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी।
- यह भारत में शीर्ष निकाय है, जो व्यापार, नीति और विकास एजेंडा पर कार्य करता है तथा व्यापार सुविधा, साझेदारी, प्रौद्योगिकी एवं कृषि व्यवसाय सेवाओं के लिये एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है

पुतिन ने हाथरस भगदड़ त्रासदी पर संवेदना व्यक्त की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक समागम में हुई भगदड़ पर शोक व्यक्त किया जिसमें 121 लोग मारे गए थे।

- भगदड़ भीड़ का एक आवेगपूर्ण सामूहिक आंदोलन है जिसके परिणामस्वरूप अक्सर चोटें और मौतें होती हैं।

मुख्य बिंदु

- भगदड़ उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई। पीड़ित हज़ारों लोगों की भीड़ का हिस्सा थे जो एक धार्मिक उपदेशक के 'सत्संग' के लिये सिकंदराराऊ क्षेत्र के फुलराई गाँव के पास एकत्र हुए थे।

- उत्तर प्रदेश पुलिस ने धार्मिक समागम के आयोजकों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की है।
 - आयोजकों पर साक्ष्य छिपाने और केवल 80,000 लोगों के उपस्थित होने की अनुमति के बावजूद 2.5 लाख लोगों को कार्यक्रम में एकत्रित होने की अनुमति देकर शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report- FIR)

- प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) एक लिखित दस्तावेज़ है जो पुलिस द्वारा तब तैयार की जाती है जब उसे किसी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना प्राप्त होती है।
- यह एक सूचना रिपोर्ट है जो समय पर सबसे पहले पुलिस तक पहुँचती है, इसीलिए इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है।
- यह आमतौर पर एक संज्ञेय अपराध के शिकार व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत होती है। कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध की सूचना मौखिक या लिखित रूप में दे सकता है।
- FIR शब्द भारतीय दंड संहिता (IPC), अपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 या किसी अन्य कानून में परिभाषित नहीं है।
 - हालाँकि पुलिस नियमों या कानूनों में CrPC की धारा 154 के तहत दर्ज की गई जानकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के रूप में जाना जाता है।

काशी में एग्री जंक्शन केंद्र खुलेंगे

चर्चा में क्यों ?

अधिकारियों के अनुसार, काशी में प्रशिक्षित युवा कृषकों के लिये 20 एग्री जंक्शन केंद्र खोले जाने हैं।

मुख्य बिंदु

- चालू वित्त वर्ष के लिये जिले का लक्ष्य युवा, प्रशिक्षित किसानों के लिये 20 एग्री जंक्शन केंद्र खोलना है।
- राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 में इस योजना की शुरुआत की थी। वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच कुल 104 केंद्र खोले गए, जिनमें से 71 वर्तमान में सक्रिय हैं।
 - कोई भी कृषि या कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक, जिसके पास किसी राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से कृषि और संबद्ध विषयों जैसे बागवानी, पशुपालन, वानिकी, डेयरी, पशु चिकित्सा, मुर्गीपालन तथा इसी तरह की गतिविधियों में डिग्री है, वह एग्री जंक्शन केंद्रों की स्थापना हेतु आवेदन करने के लिये पात्र होगा।
- इसके अलावा, कृषि में अनुभवी डिप्लोमा धारक, इंटरमीडिएट योग्यताधारी उम्मीदवारों पर भी विचार किया जाएगा।
- चयन के बाद लाभार्थियों को ग्रामीण व्यवसाय विकास योजना (RIDP) में 13 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
 - RIDP व्यवसाय स्थानांतरण और विस्तार प्रयासों को समर्थन देने हेतु स्थानीय विकास निगमों के माध्यम से अनुदान निधि प्रदान करता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (The Indian Council of Agricultural Research- ICAR)

- इसकी स्थापना 16 जुलाई, 1929 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।
- यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (Department of Agricultural Research and Education- DARE), कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

- यह 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा तथा अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण एवं रखरखाव के लिये भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और दस अन्य सदस्यों की नियुक्ति करती है।
- अध्यक्ष का चयन ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जो केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी नहीं होते।

उत्तर प्रदेश सरकार का रक्षा सौदा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए के 154 से अधिक रक्षा विनिर्माण सौदों पर हस्ताक्षर किये हैं।

मुख्य बिंदु

- रक्षा मंत्रालय (MoD) के अनुसार, 2023-24 (वित्त वर्ष 24) में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.27 ट्रिलियन रुपए है, जो 2023 की तुलना में 16.7% अधिक है।
- विशाल उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा (UPDIC), जो लखनऊ, कानपुर, झाँसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा जिलों में छह नोड्स तक विस्तृत है, में रक्षा परियोजनाओं का विकास हो रहा है।
 - कॉरिडोर की नोडल एजेंसी UP एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) ने अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस, ब्रह्मोस एयरोस्पेस, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) आदि विभिन्न कंपनियों के साथ 154 समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।
- उत्तर प्रदेश अपनी 'मेक इन UP' पहल को आगे बढ़ाने के लिये रक्षा विनिर्माण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।
 - राज्य का लक्ष्य इस प्रयास को गति देने हेतु अपने व्यापक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) आधार का लाभ उठाना है।
- उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कोरवा कारखाने में निर्मित कुल 35,000 कलाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफलें इंडो-रूस राइफलस प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त उद्यम द्वारा भारतीय सेना को दी गई हैं।
- भारतीय रक्षा बलों के लिये ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्माण हेतु लखनऊ में एक और इंडो-रूस संयुक्त उद्यम संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।
 - ब्रह्मोस भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और रूस के गैर-लाभकारी संगठन मशीनोस्ट्रोयेनिया (NPOM) के बीच एक संयुक्त उद्यम है जिसका उद्देश्य भारतीय सेनाओं के लिये अगली पीढ़ी की सुपरसोनिक मिसाइलों का विकास करना है।

उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा (UPDIC):

- यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करना है। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में हुआ था।
- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) को राज्य की विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर इस परियोजना को निष्पादित करने के लिये नोडल एजेंसी बनाया गया था।
- इसमें 6 नोड्स शामिल होंगे- अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झाँसी और लखनऊ।
- इस कॉरिडोर/गलियारे का उद्देश्य राज्य को सबसे बड़े और उन्नत रक्षा विनिर्माण केंद्रों में से एक के रूप में स्थापित करना एवं विश्व मानचित्र पर लाना है।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA)

- यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकास के लिये वर्ष 2007 में स्थापित एक प्राधिकरण है।
- UPEIDA का मुख्यालय लखनऊ के गोमती नगर स्थित पर्यटन भवन में स्थित है।

भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **श्री जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा** समिति कीडंगज के तत्वावधान में प्रयागराज में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु:

- रथ यात्रा कीडंगज में त्रिवेणी मार्ग स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से शुरू हुई।
 - भगवान जगन्नाथ के नंदीघोष रथ के अलावा गरुड़ देव, बद्री विशाल, भगवान राम और भगवान द्वारकाधीश के रथ भी शोभायात्रा का हिस्सा रहे
 - रथयात्रा में राधा कृष्ण, नरसिंह अवतार और दामोदर लीला को दर्शाती झांकियाँ भी शामिल रहीं।
- जगन्नाथ रथ यात्रा एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी छोटी बहन देवी सुभद्रा की ओडिशा के पुरी में उनके घरेलू मंदिर से लगभग तीन किलोमीटर दूर गुंडिचा में उनकी मौसी के मंदिर तक की यात्रा का उत्सव मनाता है।
 - इस त्योहार के पीछे किंवदंती है कि एक बार देवी सुभद्रा ने गुंडिचा में अपनी मौसी के घर जाने की इच्छा व्यक्त की।
 - उनकी इच्छा पूरी करने के लिये भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र ने उनके साथ रथ यात्रा पर जाने का निर्णय किया। इस घटना को प्रति वर्ष देवताओं को इसी तरह की यात्रा पर ले जाकर मनाया जाता है।
- इस त्योहार की शुरुआत कम-से-कम 12वीं शताब्दी ई. से हुई है, जब राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। हालाँकि कुछ स्रोतों से पता चलता है कि यह त्योहार प्राचीन काल से ही प्रचलित था।
- इस त्योहार को रथों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि देवताओं को तीन विशाल लकड़ी के रथों पर ले जाया जाता है, जिन्हें भक्त रस्सियों से खींचते हैं।
- यह आषाढ़ (जून-जुलाई) माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शुरू होता है और नौ दिनों तक चलता है।

जगन्नाथ पुरी मंदिर



- यह भारतीय राज्य ओडिशा के सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक है।
- यह मंदिर “सफेद पैगोडा” के नाम से जाना जाता है और यह चार धाम तीर्थयात्राओं (ब्रह्मनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम) का एक हिस्सा है।
- यह कलिंग वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है, जो घुमावदार मीनारों, जटिल नक्काशी और अलंकृत मूर्तियों से पहचाना जाता है।
- मंदिर परिसर चारों ओर से ऊँची दीवार से घिरा हुआ है तथा इसके चारों दिशाओं की ओर चार द्वार हैं।
- मुख्य मंदिर में चार संरचनाएँ हैं: विमान (गर्भगृह), जगमोहन (सभा कक्ष), नट-मंदिर (उत्सव कक्ष) और भोग-मंडप (अर्पण कक्ष)।
- जगन्नाथ पुरी मंदिर को ‘यमनिका तीर्थ’ कहा जाता है, जहाँ हिंदू मान्यताओं के अनुसार, भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण पुरी में मृत्यु के देवता ‘यम’ की शक्ति समाप्त हो गई है।

दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर उत्तर प्रदेश

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 3-4 वर्षों में दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर होना है, जिसमें वर्ष 2016 से 36% की वृद्धि हुई है। सरकार अरहर, उड़द और मूंग की खेती पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2016-2017 से वर्ष 2023-2024 के दौरान दालों का उत्पादन 2.394 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 3.255 मिलियन मीट्रिक टन हो गया।
 - दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत 27,200 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल प्रदर्शन आयोजित किये जाएंगे।
 - 31,553 क्विंटल बीज वितरण तथा 27,356 क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
- बाज़ार में दलहनी फसलों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिये सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP) पर इन सभी फसलों की खरीद भी सुनिश्चित कर रही है।
- सूत्रों के अनुसार बुंदेलखंड के प्रमुख दलहन उत्पादन जिलों बाँदा, महोबा, जालौन, चित्रकूट और ललितपुर में आदर्श दलहन गाँव विकसित किये जाएंगे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(National Food Security Mission- NFSM)

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(National Food Security Mission- NFSM) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council- NDC) की कृषि उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2007 में शुरू किया गया था।
- समिति ने उन्नत कृषि विस्तार सेवाओं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विकेंद्रीकृत योजना की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) को एक मिशन मोड कार्यक्रम के रूप में संकल्पित किया गया।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP)

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह गारंटीकृत राशि है जो सरकार द्वारा किसानों की उपज खरीदने पर उन्हें दी जाती है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices- CACP) की सिफारिशों पर आधारित है, जो उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाज़ार मूल्य प्रवृत्तियों, अंतर-फसल मूल्य समता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है।
 - कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया।

- भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में **आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs- CCEA)** न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के स्तर पर अंतिम निर्णय (अनुमोदन) लेती है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी उपज के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और **फसल विविधीकरण** को प्रोत्साहित करना है।

वाराणसी में ब्लैक कार्बन के स्तर में कमी

चर्चा में क्यों ?


बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के एक अध्ययन के अनुसार, वाराणसी और **मध्य गंगा के मैदानी भागों** में कार्बन स्तर में 0.47 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत वार्षिक गिरावट देखी गई है।

मुख्य बिंदु

- अध्ययन में **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO)** के **एयरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग ओवर इंडिया (Aerosol Radiative Forcing over India- ARFI)** कार्यक्रम के तहत उत्पन्न ब्लैक कार्बन डेटा का उपयोग किया गया।
 - मध्य भारत-गंगा के मैदान, वाराणसी में एक प्रतिनिधि स्थान पर वर्ष 2009 से वर्ष 2021 तक **ब्लैक कार्बन** द्रव्यमान सांद्रता के एक दशक लंबे माप का विश्लेषण किया गया।
 - इस विश्लेषण का उद्देश्य इस क्षेत्र में **ब्लैक कार्बन के भौतिक, प्रकाशीय और विकिरणीय प्रभाव** को समझना था।
- अध्ययन में **ब्लैक कार्बन के स्तर में 0.47 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत वार्षिक कमी दर्ज की गई**
 - ब्लैक कार्बन के स्तर में भी लगातार **मौसमी गिरावट** देखी गई, जिसमें **मानसून के बाद औसत कमी 1.86 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर** तथा **मानसून से पूर्व औसत कमी 0.31 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर** रही।
- अध्ययन में पाया गया कि वाराणसी और मध्य गंगा के मैदानों में **ब्लैक कार्बन का स्रोत स्थानीय नहीं बल्कि दूरवर्ती स्रोत हैं**।
 - ये कण निचले और ऊपरी सिंधु-गंगा के मैदानों, **पाकिस्तान, मध्य पूर्व और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों** से लंबी दूरी तक स्थानांतरित होते हैं।

WHAT IS BLACK CARBON


Black carbon, also known as soot, is a black, carbon-rich substance emitted from gas and diesel engines, coal-based power plants, and other sources that burn fossil fuels. It forms due to incomplete combustion of wood and fossil fuels, producing carbon dioxide (CO₂), carbon monoxide, and volatile organic compounds. Black carbon is a significant component of particulate matter (PM-2.5), a harmful air pollutant. It warms the atmosphere by effectively absorbing light



IMPACT ON HEALTH

- PM 2.5 air pollution is linked to lung diseases, stroke, heart attacks, chronic respiratory diseases like bronchitis, asthma, and premature deaths in adults suffering from heart & respiratory conditions
- It also affects children, contributing to premature deaths from acute lower respiratory infections like pneumonia
- These particles have been found in lungs, liver, and brain of unborn babies, potentially affecting early childhood development

- Black carbon is a major environmental cause of poor health & premature deaths
- Particles, which are much smaller than grains of table salt, can penetrate deep into the lungs, and transport toxic compounds into the bloodstream



ब्लैक कार्बन

- ब्लैक कार्बन (Black Carbon- BC) एक अल्पकालिक प्रदूषक है जो कार्बन डाइ-ऑक्साइड (CO₂) के बाद ग्रह को गर्म करने में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
- अन्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के विपरीत ब्लैक कार्बन तेजी से प्रक्षालित हो जाता है और उत्सर्जन बंद होने पर वायुमंडल से समाप्त किया जा सकता है।
- ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन के विपरीत यह भी एक स्थानीय स्रोत है जिसका स्थानीय प्रभाव अधिक है।
- ब्लैक कार्बन एक प्रकार का एयरोसोल है।

न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का शीघ्र पता लगाना

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) वाराणसी के शोधकर्ताओं ने एक अभूतपूर्व 'लैब-ऑन-चिप' उपकरण विकसित किया है, जो उल्लेखनीय सटीकता के साथ प्रारंभिक चरण की बीमारियों का पता लगा सकता है।

मुख्य बिंदु

- यह नवोन्मेषी सफलता पार्किंसंस रोग, अवसाद और सिज़ोफ्रेनिया जैसी तंत्रिका (Neurological) संबंधी स्थितियों की तीव्र तथा अधिक विश्वसनीय पहचान को सक्षम करके स्वास्थ्य सेवा में बदलाव लाने की क्षमता रखती है।
- IIT-BHU स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ऊर्जा उपकरणों के लिये नैनोमटेरियल (Nanomaterials for Electronics and Energy Devices- NEED) प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा किये गए इस नवाचार में मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को समझने में क्रांतिकारी बदलाव लाने तथा प्रारंभिक अवस्था में ही तंत्रिका संबंधी विकारों (न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर) के लिये नए उपचार का मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता है।
- नव विकसित उपकरण में धातु के नैनोकणों से सुसज्जित, परमाण्विक रूप से पतले, द्वि-आयामी (2D) अर्द्धचालक को शामिल किया गया है, जो उन्नत सर्फेस-एन्हांसड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी (SERS) प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है।
 - इससे डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की सूक्ष्म सांद्रता का पता अद्वितीय परिशुद्धता और गति से लगाया जा सकता है।
- इस तरह के नवाचार के निहितार्थ बहुत गहन हैं, जहाँ नवीन सामग्रियों का विकास करना और उन्हें उपकरण में परिवर्तित करना, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित उपकरण निर्माण के विभिन्न राष्ट्रीय मिशनों को संभावित रूप से सहायता प्रदान कर सकता है।

सर्फेस-एन्हांसड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी (SERS)

- SERS आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एक सेंसिंग तकनीक है, जिसमें अणुओं द्वारा बिखरे हुए इनलेस्टिक लाइट (Aelastic Light) की तीव्रता को तब बढ़ाया जाता है, जब तक अणुओं को सिल्वर या गोल्ड नैनोपार्टिकल्स (NPs) जैसी नालीदार धातु की सतहों पर अवशोषित किया जाता है।
- यह अणुओं में रमन प्रकीर्णन प्रकाश (Raman Scattering Light) की तीव्रता को तेज करता है, जिससे अणुओं का प्रभावी विश्लेषण होता है।

पार्किंसंस रोग

- पार्किंसंस रोग एक प्रोग्रेसिव न्यूरोडीजेनेरेटिव डिसऑर्डर है जो गतिशीलता को बाधित करता है और समय के साथ गतिहीनता एवं मनोभ्रंश का कारण बन सकता है।
 - यह बीमारी आमतौर पर वृद्ध लोगों को होती है, लेकिन युवा लोग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुष इससे अधिक प्रभावित होते हैं।
 - पिछले 25 वर्षों में पार्किंसंस की व्यापकता दोगुनी हो गई है। पार्किंसंस रोग के वैश्विक बोझ में भारत का हिस्सा लगभग 10% है।

सिज़ोफ्रेनिया

- यह एक गंभीर मानसिक विकार है, जिसमें सोचने-समझने में बहुत ज्यादा व्यवधान होता है, जिससे भाषा, धारणा और आत्म-बोध प्रभावित होता है। यह दुनिया भर में 21 मिलियन से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है।
- शोधकर्ताओं का मानना है कि आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक, जैसे वायरस के संपर्क में आना, इसके कारण-कार्य में योगदान करते हैं तथा जीवन के तनाव भी इस विकार की शुरुआत एवं प्रगति में भूमिका निभा सकते हैं।

हाइब्रिड कारों पर कोई रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ करने का निर्णय किया है। यह निर्णय ग्रीन वाहनों के लिये एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है।

मुख्य बिंदु

- इस कदम से मुख्य रूप से मारुति सुजुकी, टोयोटा किलोस्कर मोटर और होंडा कार्स इंडिया जैसी कार निर्माता कंपनियों को लाभ होगा। ग्राहक 3.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश में 10 लाख रुपए से कम मूल्य के वाहनों पर 8% रोड टैक्स तथा 10 लाख रुपए (एकस-शोरूम) से अधिक मूल्य के वाहनों पर 10% रोड टैक्स लगाया जाता है।
 - हाइब्रिड वाहनों की कम बिक्री के कारण सड़क कर माफी से राज्य के राजस्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।
- स्वामित्व में आसानी इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की तरह समर्पित चार्जिंग बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता नहीं, पेट्रोल कारों की तुलना में बेहतर माइलेज और कम अधिग्रहण लागत जैसे कारकों के कारण हाइब्रिड वाहनों की बिक्री में तेज़ी आ रही है।
 - वर्ष 2023 में राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिये तीन वर्ष की टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क छूट की घोषणा की, जबकि राज्य के भीतर निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये पाँच वर्ष की छूट दी जाएगी।

हाइब्रिड वाहन

- हाइब्रिड वाहन पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (Internal Combustion Engine- ICE) को इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के साथ जोड़ते हैं, जिससे वाहन को एक या दोनों ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके संचालित करने की अनुमति मिलती है।
- हाइब्रिड प्रणालियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन सबसे आम हैं समानांतर हाइब्रिड (इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों ही वाहन को स्वतंत्र रूप से शक्ति प्रदान कर सकते हैं) तथा श्रृंखला हाइब्रिड (केवल इलेक्ट्रिक मोटर पहियों को चलाती है, जबकि इंजन विद्युत उत्पन्न करता है)।

आम की प्रूनिंग का परमिट रद्द

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को आम के वृक्षों की छँटाई/प्रूनिंग के लिये किसी भी सरकारी विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता से छूट देने का निर्णय लिया।

- आम उत्पादक अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिये पेड़ों की छँटाई कर सकते हैं और उनकी ऊँचाई कम कर सकते हैं।

मुख्य बिंदु:

- इस निर्णय से पुराने आम के बागों के लिये कैनेपी प्रबंधन आसान हो गया है। इससे पुराने आम के बागों का कायाकल्प हो जाएगा और वे नए बागों की तरह उत्पादक बन जाएंगे।
 - पुराने बागों में नई पत्तियों और शाखाओं की वृद्धि में कमी आ गई है, जो फूल तथा फल के लिये महत्वपूर्ण है।
 - इसके बजाय, मोटी और उलझी हुई शाखाएँ अधिक हैं, जो पर्याप्त प्रकाश को अंदर तक पहुँचने से रोकती हैं।

- इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप कीटों और बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है तथा **कीटनाशकों** का प्रभावी प्रयोग जटिल हो जाता है।
 - परिणामस्वरूप, छिड़काव किये गए कीटनाशक अक्सर पेड़ों के अंदरूनी हिस्सों तक पहुँचने में विफल हो जाते हैं, जिससे कीटनाशकों का उपयोग बढ़ जाता है और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाता है।
- इन समस्याओं से निपटने के लिये **केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (Central Institute of Subtropical Horticulture- CISH)** ने आम के वृक्षों को पुनर्जीवित करने हेतु एक प्रभावी छँटाई तकनीक विकसित की है।
 - इस विधि को **तृतीयक शाखाओं की छँटाई** या टेबल-टॉप प्रूनिंग कहा जाता है, जिससे वृक्ष की कैनोपी खुल जाती है, उसकी ऊँचाई कम हो जाती है तथा **स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा** मिलता है।
 - इस छँटाई तकनीक (Pruning Technique) से वृक्षों से 2-3 वर्षों में ही 100 किलोग्राम तक उपज प्राप्त की जा सकती है, साथ ही अत्यधिक कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता भी कम हो जाती है।

केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान (CISH)

- इसे 4 सितंबर, 1972 को **भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु** के तत्वावधान में **केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र** के रूप में शुरू किया गया था।
- संस्थान, जिसका नाम बाद में 14 जून, 1995 को केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान (Central Institute for Subtropical Horticulture- CISH) रखा गया, उपोष्णकटिबंधीय फलों पर अनुसंधान के सभी पहलुओं पर राष्ट्र की सेवा कर रहा है।
- CISH का **मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश** में स्थित है।

सारस क्रेन की संख्या में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

राज्य वन विभाग द्वारा की गई गणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में **सारस क्रेन** की संख्या बढ़ रही है।

मुख्य बिंदु:

- सर्वेक्षण से पता चला कि **इटावा वन प्रभाग** में **सारस क्रेन** की संख्या सबसे अधिक 3,289 दर्ज की गई, जो कि 500 अधिक है।
 - जबकि मऊ वन प्रभाग ने एक दशक में पहली बार छह सारस क्रेन देखे।
- उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की संख्या पिछले कुछ वर्षों में निरंतर बढ़ी है और वर्ष 2021 में 17,329 से बढ़कर वर्ष 2022 में 19,188, वर्ष 2023 में 19,522 तथा वर्ष 2024 में 19,918 हो गई है।

सारस क्रेन

- सारस क्रेन का वैज्ञानिक नाम **ग्रस एंटीगोन (Grus Antigone)** है।
- यह विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, जिसकी लंबाई 152-156 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 240 सेंटीमीटर है।
- सारस क्रेन मुख्य रूप से लाल सिर और इसकी ऊपरी गर्दन भूरे रंग की होती है, साथ ही हल्के लाल पैर होते हैं।
- यह आजीवन जोड़े में रहते हैं और इसना प्रजनन काल **मानसून** में भारी बारिश के दौरान होता है।
- ये मनुष्यों के साथ और अच्छी तरह से जल वाले मैदानों, दलदली भूमि, तालाबों तथा **आर्द्रभूमि** (जैसे उत्तर प्रदेश में धनौरी आर्द्रभूमि) में रहने के लिये जाने जाते हैं जो उनके निर्वहन तथा घोंसले के लिये उपयुक्त हैं।
- **संरक्षण की स्थिति:**
 - ◆ **IUCN रेड लिस्ट:** सुभेद्य
 - ◆ **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची IV



अल्ट्रा हाई-परफॉर्मेंस कंक्रीट- UHPC

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (Public Works Department- PWD) अनुसंधान और विकास के बाद अल्ट्रा हाई-परफॉर्मेंस कंक्रीट (UHPC) विकसित करने के लिये IIT-कानपुर के साथ समझौता करेगा।

मुख्य बिंदु:

- वर्तमान में राज्य में अधिकांश सिविल कार्यों हेतु M60 सीमेंट ग्रेड का उपयोग किया जाता है।
- UHPC, जिसकी शैल्फ लाइफ लंबी होती है और जो M60 ग्रेड की तुलना में 4-6 गुना अधिक मजबूत हो सकती है तथा विभाग के कार्बन फुटप्रिंट को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकती है।
 - इस कमी को प्राप्त करने के लिये, फ्लाइओवर, एलिवेटेड रोडवेज, रेलवे ओवरब्रिज, पुल तथा अन्य कंक्रीट-गहन बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के विकास में पतले खंडों एवं कम डेक ऊँचाइयों का उपयोग किया जाएगा।
 - नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित इस उत्पाद के तीन वर्षों में तैयार होने का अनुमान है।

कार्बन फुटप्रिंट

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) के अनुसार, कार्बन फुटप्रिंट लोगों की गतिविधियों के कारण जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव का एक माप है और इसे टन में उत्पादित CO₂ उत्सर्जन के भार के रूप में व्यक्त किया जाता है।

नोट :

- इसे आमतौर पर प्रतिवर्ष उत्सर्जित CO₂ के टन के रूप में मापा जाता है, यह एक ऐसी संख्या है जिसे **मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों** सहित CO₂-समतुल्य गैसों के टन से पूरा किया जा सकता है।
- यह एक व्यापक उपाय हो सकता है या इसे किसी व्यक्ति, परिवार, घटना, संगठन अथवा यहाँ तक कि पूरे राष्ट्र के कार्यों पर लागू किया जा सकता है।

दृष्टिहीनों के लिये नया यूज़र इंटरफ़ेस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Information Technology- IIT)**, इलाहाबाद के विशेषज्ञों ने जर्मनी के कार्ल्सरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सहयोग से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिये चार्ट चित्र बनाने और उन तक पहुँचने के लिये एक उपकरण विकसित किया है।

मुख्य बिंदु:

- इस उपकरण का उपयोग अंधे लोग छवियों को खोजने और उन्हें **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** आधारित सॉफ्टवेयर द्वारा उत्पन्न वैकल्पिक पाठ (**Alt-text**) के साथ समझने के लिये कर सकते हैं।
- 'ऑल्ट4 ब्लाइंड: ए यूजर इंटरफ़ेस टू सिंप्लीफ़ाई चाट्स ऑल्ट-टेक्स्ट क्रिएशन' शीर्षक वाले शोध-पत्र में ऑस्ट्रिया के लिंज़ में विशेष ज़रूरतों वाले लोगों की मदद करने वाले कंप्यूटरों पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चर्चित शोध कार्य को प्रस्तुत किया गया है।
 - वैकल्पिक पाठ (**Alt-text**) को लेखकों द्वारा मैन्युअल रूप से तैयार किया जाता है, लेकिन इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप प्रायः अतिसरलीकरण अथवा अतिजटिलता जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- उभरते रुझानों में Alt-Text के निर्माण के लिये AI प्रौद्योगिकी को अपनाया जा रहा है।
 - रिसर्च में AI इमेज रिट्रीवल का उपयोग करके वैकल्पिक टेक्स्ट राइटिंग को बेहतर बनाने के लिये एक ऑनलाइन, ओपन-सोर्स टूल प्रस्तुत किया गया, जिससे इसे और अधिक आकर्षक बनाया जा सके।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI)

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मशीनों और प्रणालियों की ज्ञान प्राप्त करने, उसे लागू करने तथा बुद्धिमान व्यवहार करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है।
 - "कृत्रिम बुद्धिमत्ता" शब्द का आविष्कार **जॉन मैकार्थी** ने किया था, जो एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और संज्ञानात्मक वैज्ञानिक थे। वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुशासन के संस्थापकों में से एक थे।
- इसमें **मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क**, कंप्यूटर विज्ञान, **लार्ज लैंग्वेज मॉडल** इत्यादि प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आदर्श विशेषता इसकी तर्कसंगतता और ऐसे कार्य करने की क्षमता है जिनसे किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना होती है।

अर्ली लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार अर्ली लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम स्थापित करने की योजना बना रही है।

- इस प्रणाली का उद्देश्य राज्य में विशेषकर मानसून के दौरान, **तड़ित (Lightning)** के कारण होने वाली जनहानि को रोकना है।

मुख्य बिंदु:

- **भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** की रिपोर्ट के अनुसार, तड़ित के कारण होने वाली मृत्यु में सभी राज्यों में से उत्तर प्रदेश सबसे आगे है।

- मुख्यमंत्री के निर्देश पर **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)** ने पूरे राज्य में **आगमन समय (ToA) तकनीक** पर आधारित अत्याधुनिक विद्युत पहचान प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया, जो समय और स्थान के बारे में अधिक सटीक है।
 - **IMD वर्तमान में** किसी क्षेत्र में तड़ित की संभावना के बारे में चेतावनी देने के लिये **रडार-आधारित प्रणालियों और उपग्रह डेटा** पर निर्भर करता है, लेकिन इसे वास्तविक समय की चेतावनी नहीं माना जाता है।
 - **ToA-आधारित प्रणाली** किसी विशेष क्षेत्र में तड़ित की संभावना का कम-से-कम **30 मिनट पहले सफलतापूर्वक पता** लगा सकती है और चेतावनी दे सकती है।
- उत्तर प्रदेश लाइटनिंग अलर्ट प्रबंधन प्रणाली तीन चरणों में स्थापित की जाएगी।
 - पहले चरण में इसे 37 जिलों में लागू किया जाएगा।
 - दूसरे और तीसरे चरण में इसे क्रमशः 20 और 18 जिलों में स्थापित किये जाने की आशा है।

रडार (रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग)

- यह एक उपकरण है जो स्थान (श्रेणी एवं दिशा), ऊँचाई, तीव्रता और गतिशील तथा स्थिर वस्तुओं की गति का पता लगाने के लिये माइक्रोवेव क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करता है
भारत मौसम विज्ञान विभाग
- IMD की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान एवं संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है।
- यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।

सौश्रुतम 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA)** के शल्य तंत्र विभाग ने सुश्रुत जयंती-2024 के अवसर पर द्वितीय राष्ट्रीय संगोष्ठी **सौश्रुतम (SAUSHRUTAM)** शल्य संगोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

मुख्य बिंदु

- **शल्य चिकित्सा के महान जनक** सुश्रुत के सम्मान में प्रतिवर्ष 15 जुलाई को सुश्रुत जयंती मनाई जाती है।
- वह काशी (लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व) के एक प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सक थे और उन्होंने चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा पर एक व्यापक पाठ्यपुस्तक 'सुश्रुत संहिता' लिखी थी।
- सुश्रुत संहिता को पाँच प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है:
 - **सूत्रस्थान (Sutrasthana)**: चिकित्सा विज्ञान और औषध विज्ञान के मूल सिद्धांतों से संबंधित प्राथमिक सिद्धांत;
 - **निदान (Nidana)**: यह रोगात्मक अवधारणाओं से संबंधित है;
 - **सरिरस्थान (Sarirasthana)**: मानव शरीर रचना विज्ञान पर;



- चिकित्सास्थानम (Chikitsasthanam): चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रबंधन पर;
- कल्पस्थानम (Kalpasthanam): विष विज्ञान पर।

काँवड़ यात्रा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों के विवादास्पद आदेशों पर रोक लगा दी, जिसके तहत काँवड़ यात्रा (पवित्र यात्रा) के मार्ग पर स्थित होटलों, दुकानों, भोजनालयों और ढाबों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया था।

मुख्य बिंदु

- काँवड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों द्वारा श्रावण माह में की जाने वाली एक हिंदू तीर्थयात्रा है।
- भक्तगण उत्तराखंड में हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री, बिहार में सुल्तानगंज, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी जैसे तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं तथा शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिये काँवड़ में गंगा जल लेकर लौटते हैं।
 - जल को शिव मंदिरों में चढ़ाया जाता है, जिसमें भारत के 12 ज्योतिर्लिंग और उत्तर प्रदेश में पुरा महादेव मंदिर तथा औषड़नाथ, प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर एवं झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर जैसे अन्य मंदिर शामिल हैं। इस अनुष्ठान को जल अभिषेक के नाम से जाना जाता है।

12 ज्योतिर्लिंग

- ज्योतिर्लिंग एक तीर्थस्थल है जहाँ भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा की जाती है।
- प्रत्येक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक अलग स्वरूप है।
- वर्तमान में भारत में 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं। ये हैं:
 - गिर, गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग
 - श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग
 - मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग
 - मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग
 - देवघर, झारखंड में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग
 - महाराष्ट्र में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग
 - तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामनाथस्वामी ज्योतिर्लिंग
 - गुजरात के द्वारका में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग
 - काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
 - त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक, महाराष्ट्र में है
 - रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग
 - महाराष्ट्र के औरंगाबाद में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग

कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करेगी, इसके लिये उन्हें 20 जुलाई, को वृक्षारोपण अभियान में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित करेगी, जिसमें 35.5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे।

मुख्य बिंदु

- **उद्देश्य:** उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य कार्बन वित्तपोषण अथवा कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना है।
- **वृक्षारोपण अभियान:** 20 जुलाई को राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसके दौरान 35.5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे।
- **कार्बन क्रेडिट:** किसानों को उनके द्वारा लगाए गए वृक्षों के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी के आधार पर कार्बन क्रेडिट मिलता है। अवशोषित किये गए प्रत्येक टन कार्बन डाइ-ऑक्साइड उत्सर्जन के लिये, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय लाभ मिलता है।
- **वृक्षों के प्रकार:** चिनार, मेलिया, डुबिया और सेमल जैसे तेजी से बढ़ने वाले वृक्षों को लगाने से किसानों को कार्बन क्रेडिट से अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर मिलता है।
- **क्रेडिट क्रय:** ये कार्बन क्रेडिट प्रत्येक पाँच वर्ष में छह अमेरिकी डॉलर प्रति क्रेडिट की दर से क्रय जाते हैं
- **लाभार्थी:** पहले चरण में छह मंडलों गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर के किसान कार्बन क्रेडिट से लाभान्वित होंगे।
- **प्रोत्साहन:** वर्ष 2024 से वर्ष 2026 के बीच 25,140 किसानों को 202 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा।
- **विभागवार वितरण:**
 - गोरखपुर: 2,406 किसानों को 34.66 करोड़ रुपए मिलेंगे।
 - बरेली: 4,500 किसानों को 24.84 करोड़ रुपए मिलेंगे
 - लखनऊ: 2,512 किसानों को 21.26 करोड़ रुपए मिलेंगे
 - मेरठ: 3,754 किसानों को 21.67 करोड़ रुपए मिलेंगे
 - मुरादाबाद: 4,697 किसानों को 38.05 करोड़ रुपए मिलेंगे
 - सहारनपुर: 7,271 किसानों को 61.52 करोड़ रुपए मिलेंगे।
- **अनुमानित कार्बन क्रेडिट:** कुल 42,19,369 कार्बन क्रेडिट अपेक्षित हैं।
- **भावी चरण:** दूसरे चरण में सात और प्रभाग शामिल होंगे तथा तीसरे चरण का लक्ष्य पूरे राज्य को कार्बन वित्तपोषण के अंतर्गत शामिल करना है
 - दूसरे चरण में सात मंडल देवीपाटन, अयोध्या, झाँसी, मिर्जापुर, कानपुर, वाराणसी और अलीगढ़ शामिल होंगे।
 - तीसरे चरण का लक्ष्य पूरे राज्य को कार्बन वित्तपोषण के दायरे में लाना है।
- **कार्बन वित्तपोषण** कार्बन उत्सर्जन को एक मौद्रिक मूल्य प्रदान करता है

उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे 3.72 करोड़ पौधे लगाए जाएँगे

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने “पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ जन अभियान-2024” शुरू किया है, जिसका लक्ष्य राज्य भर में नदी तटों पर 3,72,66,000 पौधे लगाना है।

मुख्य बिंदु

- **शामिल किये गए नदी तट**
 - **गंगा:** गंगा नदी के किनारे 5,096.42 हेक्टेयर भूमि पर 77.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे।
 - **यमुना:** यमुना नदी के किनारे 534 स्थानों पर 98.47 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जो 6,581.32 हेक्टेयर भूमि को कवर करेंगे
 - **हिंडन:** 270.13 हेक्टेयर भूमि पर चार लाख पौधे हिंडन नदी की शोभा बढ़ाएंगे।
- **प्रोत्साहन योजना:** प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, फतेहपुर, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही, काशी वन्यजीव और बलिया सहित गंगा के किनारे वन प्रभागों में, स्वच्छ गंगा के लिये राष्ट्रीय मिशन द्वारा वित्त पोषित एक प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है।

- वृक्षों की किस्में: नदी के किनारों पर नीम, सहजन, इमली, अर्जुन, जामुन, बेल, आम, महुआ, सागौन, शीशम, गुतील, बाँस, पीपल, पक्कड़ और बरगद सहित विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाए जाएंगे।
- औषधीय पौधे: यह पहल नर्सरियों के सहयोग से 2,500 हेक्टेयर निजी भूमि पर औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती को भी बढ़ावा देती है।
- यह प्रयास न केवल राज्य के हरित आवरण को बढ़ाता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देता है।

उत्तर प्रदेश के लिये औद्योगिक लाभ

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय बजट 2024 को उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, उद्योगपतियों और व्यापारियों ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है, जिन्होंने वित्त मंत्री के निर्णयों की साहसिक तथा आशाजनक बताते हुए प्रशंसा की है।

- उन्हें विश्वास है कि इससे उत्तर प्रदेश को काफी लाभ होगा, क्योंकि इससे वह कुशल कार्यबल, बढ़ी हुई सहायता और विभिन्न क्षेत्रों में खर्च के साथ विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- सूत्रों के अनुसार, शहरी आवास परियोजनाओं के लिये 10 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में किफायती आवास की कमी को दूर करना है।
 - प्रधानमंत्री 2.0 आवास योजना से निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को लाभ मिलेगा, जबकि निजी भागीदारी के माध्यम से किराये के आवास को बढ़ावा देने से शहरी मलिन बस्तियों को कम करने में मदद मिलेगी।
- महिलाओं पर लक्षित पहलों को प्राथमिकता देना लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम है
- कृषि, नवाचार, सुधार और अन्य क्षेत्रों को कवर करने वाले नौ प्रमुख फोकस क्षेत्र सतत् प्रगति के लिये एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करते हैं।
- मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने से उत्तर प्रदेश के कई छोटे व्यवसाय मालिकों को पर्याप्त सहायता मिलेगी।
 - विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिभागियों के लिये ऋण गारंटी योजना उन्हें नई प्रौद्योगिकियों और उपकरणों में निवेश करने के लिये प्रेरित करेगी।
 - वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) तथा आयकर अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना स्टार्ट-अप और युवा व्यवसाय मालिकों के लिये लाभदायक होगा।
- कृषि क्षेत्र के लिये 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये एक नई क्लस्टर योजना की घोषणा से देश में प्रमाणीकरण तथा ब्रांडिंग के माध्यम से दलहन एवं तिलहन के उत्पादन का विस्तार होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना

- इसे 25 जून, 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिये आवास उपलब्ध कराना है।
- इसका कार्यान्वयन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया।
- विशेषताएँ:
 - पात्र शहरी गरीबों को पक्का मकान सुनिश्चित करके झुग्गीवासियों सहित शहरी गरीबों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करना।

- मिशन में **संपूर्ण शहरी क्षेत्र शामिल है**, जिसमें सांविधिक कस्बे, अधिसूचित योजना क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के तहत कोई भी ऐसा प्राधिकरण शामिल है, जिसे शहरी नियोजन एवं विनियमन का कार्य सौंपा गया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अंतर्गत सभी घरों में **शौचालय, जलापूर्ति, विद्युत और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।**
- मिशन महिला सदस्यों के नाम पर या संयुक्त नाम पर मकान का स्वामित्व प्रदान करके **महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा** देता है।
- इसके अतिरिक्त **दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर एवं असुरक्षित वर्गों को भी प्राथमिकता दी जाती है।**

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana- PMMY)

- इसे सरकार द्वारा वर्ष 2015 में गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिये लॉन्च किया गया था।
- वित्तपोषण प्रावधान:
 - मुद्रा (MUDRA), जिसका पूरा नाम **माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड** है, सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था है।
 - यह बैंकों, **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies- NBFC)** और **सूक्ष्म वित्त संस्थानों (Micro Finance Institutions- MFI)** जैसे विभिन्न अंतिम-मील वित्तीय संस्थानों के माध्यम से गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्तपोषण प्रदान करता है।
 - मुद्रा योजना सूक्ष्म उद्यमियों/व्यक्तियों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देती है।

वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय का ब्राज़ील के साथ समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मेरठ स्थित श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने दोनों देशों के विद्यार्थियों के बीच शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिये ब्राज़ील के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- इसका मुख्य ध्यान केंद्रण **डेयरी, कृषि, जैवप्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पर्यटन** के क्षेत्रों में विद्यार्थी और संकाय विनिमय कार्यक्रमों पर होगा।
- दोनों देश संयुक्त सेमिनारों, कार्यशालाओं और नियमित कक्षाओं के माध्यम से उन्नत प्रौद्योगिकियों और नवाचारों पर सहयोग करेंगे।
- इस साझेदारी को विद्यार्थियों के लिये उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

IIT-कानपुर के प्रोफेसर ने बहिर्ग्रह (Exoplanet) की खोज की

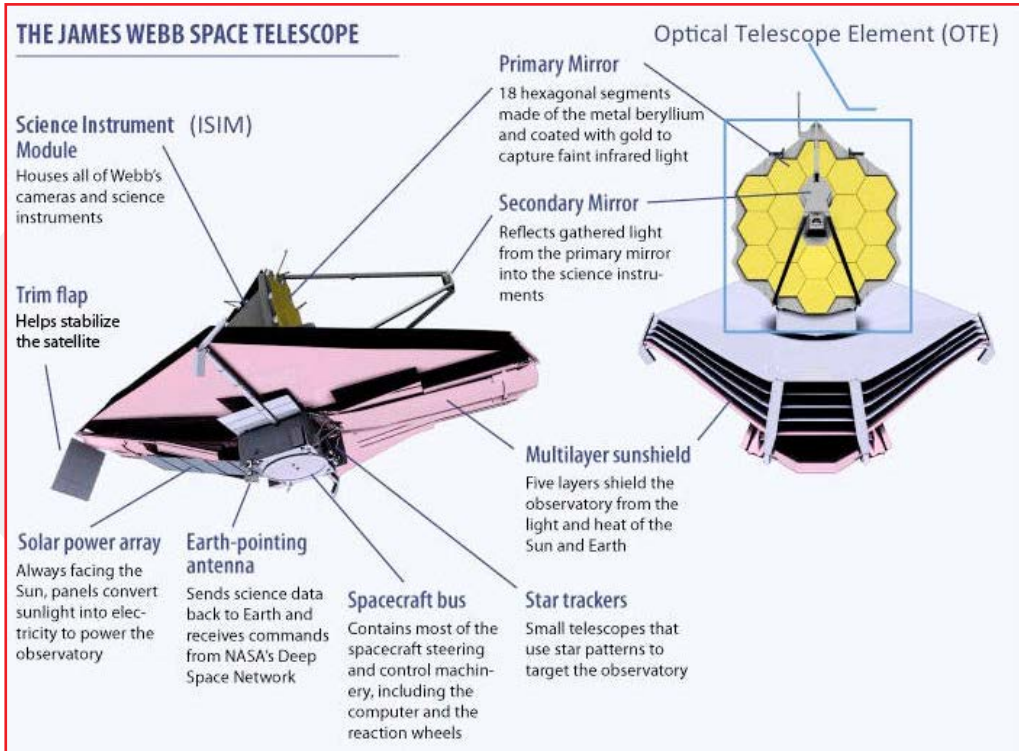
चर्चा में क्यों ?

IIT-कानपुर के अंतरिक्ष, ग्रहीय एवं खगोलीय विज्ञान तथा अभियांत्रिकी विभाग (Space, Planetary & Astro-nomical Sciences & Engineering- SPASE) के एक सहायक प्रोफेसर सहित खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक बड़े बहिर्ग्रह की खोज की है जो हमारे सूर्य के समान एक निकटवर्ती तारे की परिक्रमा कर रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- वैज्ञानिक पत्रिका नेचर के अनुसार, **एप्सिलॉन इंडी एब या एप्स इंड एब** के नाम से जाना जाने वाला सौर मंडल के बाहर का ग्रह, **बृहस्पति से कम से कम छह गुना अधिक द्रव्यमान होने के कारण 'सुपर-बृहस्पति'** के रूप में वर्गीकृत है।

- एप्स इंड एब प्रत्यक्ष चित्रण तकनीक का उपयोग करके खोजा गया पहला परिपक्व बहिर्ग्रह (हमारे सौर मंडल के बाहर का ग्रह) है।
- **जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप** के मिड-इन्फ्रारेड उपकरण का उपयोग करते हुए, खगोलविदों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने **K5V-प्रकार के तारे एप्सिलॉन इंडी A** (जिसे HD 209100 या HI के नाम से भी जाना जाता है) की परिक्रमा कर रहे एक नए बहिर्ग्रह का प्रत्यक्ष चित्र लिया है।
 - निकटवर्ती परिपक्व बहिर्ग्रह का प्रत्यक्ष चित्रण, अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- हाल ही में पहचाना गया यह ग्रह पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और अत्यंत शीतल है, जिसका तापमान लगभग -1°C (30°F) है।
 - इसकी कक्षा भी बहुत बड़ी है, जिसका आकार पृथ्वी और सूर्य की दूरी का 28 गुना है।



भारत में 628 बाघों की मृत्यु

चर्चा में क्यों ?

सरकार के आँकड़ों के अनुसार, विगत पाँच वर्षों में भारत में प्रकृत्या, अवैध शिकार सहित अन्य कारणों से कुल 628 बाघों की मृत्यु हुई।

मुख्य बिंदु

- **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** के अनुसार, वर्ष 2019 में 96, वर्ष 2020 में 106, वर्ष 2021 में 127, वर्ष 2022 में 121 और वर्ष 2023 में 178 बाघों की मृत्यु हुई।
 - इस अवधि के दौरान बाघों द्वारा किये गए हमलों से 349 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से 200 मामले मात्र महाराष्ट्र से थे।
 - उत्तर प्रदेश में बाघों के हमलों से 59 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि मध्य प्रदेश में 27 लोगों की मृत्यु हुई।

- भारत ने बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये 1 अप्रैल, 1973 को **प्रोजेक्ट टाइगर** लॉन्च किया था।
 - वर्तमान में भारत में 55 बाघ अभयारण्य हैं, जो 78,735 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत हैं जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% है।

बाघ

रॉयल बंगाल टाइगर (*Panthera Tigris*) भारत का राष्ट्रीय पशु है।

बाघ की उप प्रजातियाँ

- * महाद्वीपीय (पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस)
- * सुंडा (पैंथेरा टाइग्रिस सोंडाइका)

प्राकृतिक अधिवास

उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सदाबहार वन, समशीतोष्ण वन, मैंग्रोव दलदल, घास के मैदान और सवाना



देश जहाँ बाघ पाए जाते हैं

- 13 बाघ रेंज देश जहाँ यह प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उनमें- भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम शामिल हैं।
- IUCN की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बाघ विलुप्त हो गए हैं।

संरक्षण की स्थिति

- IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय
- CITES: परिशिष्ट-I
- WPA 1972: अनुसूची-I

संरक्षण संबंधी प्रयास

- इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस (IBCA): बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा नामक सात बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिये (भारत द्वारा शुरू)
- Tx2 अभियान: WWF द्वारा आरंभ किया गया; 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने के लक्ष्य को इंगित करते हुए 'टाइगर टाइम्स 2' को संदर्भित करता था
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA): WPA, 1972 के तहत गठित
- प्रोजेक्ट टाइगर: 1973 में लॉन्च किया गया
- बाघों की गणना: प्रत्येक 5 वर्ष में

खतरे

- आवास विखंडन
- अवैध शिकार
- मानव-वन्यजीव संघर्ष

भारत में बाघ

- भारत में इनकी संख्या सबसे अधिक है
 - वर्ष 2022 तक, भारत में बाघों की संख्या 3167 थी
 - मध्य भारतीय उच्च भूमि और पूर्वी घाट में इनकी सबसे बड़ी आबादी पाई गई है
- टाइगर रिजर्व: भारत में अब 53 टाइगर रिजर्व हैं
 - नवीनतम टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का रानीपुर है
 - नागार्जुन सागर (आंध्र प्रदेश) सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जबकि ओरंग (असम) सबसे छोटा (कोर क्षेत्र) है।



Drishti IAS

